दिनांक–17 सितम्बर 2025 **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर आज से हो रही है 'सेवा पर्व' की शुरुआत। ''स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार'' और आठवें पोषण माह अभियान का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री।
- सेवारत बेसिक शिक्षकों के लिये टीईटी की अनिवार्यता के सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी प्रदेश सरकार।
- प्रदेश के विभिन्न जिलों में खुलेंगे संत कबीर वस्त्र और परिधान पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश।
- प्रदेश में परिवहन विभाग ने रद्द किए वर्ष दो हजार सत्रह से लेकर दो हजार इक्कीस के बीच जारी किए गए गैर कर ई–चालान।

****

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पचहत्तरवें जन्मदिन पर आज "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान" और आठवें पोषण माह का शुभारंभ करेंगे। इसी क्रम में आज से दो अक्टूबर तक प्रदेशभर में सेवा पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार इस दौरान पंद्रह लाख पौधरोपण और स्वच्छ उत्सव जैसे कई अभियान चलाएगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट–

सेवा पर्व के दौरान सरकार पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेगी। इसके तहत स्वास्थ्य शिविर, पोषण जागरूकता और मातृत्व लाभ वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। अभियान के तहत लोगों को संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में स्वास्थ्य कैंप और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे।नगर विकास विभाग की तरफ से "स्वच्छता ही सेवा 2025" पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। वहीं वन विभाग सेवा पर्व के दौरान प्रदेश में 15 लाख पौधरोपण कराएगा। इसमें सभी 34 नगर वन में कम से कम 100 पौधे रोपित किए जाएंगे। साथ ही वन विभाग सेवा पर्व को स्वच्छ उत्सव के रूप में भी मनाएगा। इस दौरान स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक विरोधी अभियान, पक्षी अभयारण्यों में सफाई के लिए भी आयोजन किए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे विषयों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।

****

जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है।

जलवायु समाधानों से लेकर हरित ऊर्जा तक, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को आकार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से जलवायु कार्रवाई के प्रयासों में ये सबसे अच्छी तरह परिलक्षित होता है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया के लिए आशा की एक बड़ी किरण बनकर उभरा है।

इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है सवा सौ करोड़ भारतीयों को इस बात की भी खुशी है कि आइसा का हेड क्वार्टर भारत में ही है। ये आइसा के प्रति अपनत्व को और बढ़ाता है।

अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लागत–प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधानों के माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जन के साथ विकास को बढ़ावा देना चाहता है। भारत की एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल में एक वैश्विक सौर ग्रिड की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक सौर संसाधनों को जोड़ना है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

****

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए तीन सितंबर को जीएसटी परिषद ने कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती का फैसला किया। कृषि क्षेत्र और खासकर ट्रैक्टरों पर जीएसटी दरों में किये गये सुधारों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट–

सरकार ने कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, ट्रैक्टर के कल पुर्जों पर जीएसटी को पहले के 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। जीएसटी में इन सुधारों से जरूरी उपकरणों की लागत में कटौती होगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार के इस फैसले से कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी। नई कर दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होगीं। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।

****

प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिवीजन याचिका दाखिल करेगी। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं। समय–समय पर सरकार की ओर से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजर अंदाज करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पहले से अध्यापन का कार्य करते आ रहे नियमित शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है।

****

प्रदेश सरकार ने राज्य के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए विभिन्न जिलों में वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में इस बारे में जरूरी निर्देश दिए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट–

प्रस्तावित योजना संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना के नाम से लागू होगी। योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल अथवा नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक पार्क न्यूनतम 50 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पारंपरिक हथकरघा और वस्त्र उत्पादों की समृद्ध धरोहर वाला राज्य है, जिसकी क्षमता का सही उपयोग होने पर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं,बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश प्रस्तावों को शीघ्र गति से क्रियान्वित करने के लिए भूमि की पहचान और विकास कार्य को तेज किया जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को इस योजना का मुख्य लक्ष्य बताया। बैठक में पॉवरलूम बुनकरों की उत्पादन लागत कम करने, आय बढ़ाने और परंपरागत वस्त्र उद्योग को नई मजबूती देने के उद्देश्य से बुनकरों के साथ संवाद करने के भी निर्देश दिए गए। समाचार कक्ष से राघवेन्द्र त्रिपाठी।

****

प्रदेश में, परिवहन विभाग ने वर्ष दो हजार सत्रह से लेकर दो हजार इक्कीस के बीच जारी किए गए गैर–कर ई–चालान को रद्द कर दिया है। एक रिपोर्ट–

अधिकारियों ने कहा कि इन चालानों से जुड़ी सभी बाधाएं जैसे फिटनेस प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण, परमिट जारी करना, वाहन स्थानांतरण और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट एचएएसआरपी स्वतः ही दूर हो जाएँगी। हालाँकि, कर से जुड़े चालान इस राहत के दायरे में नहीं आएंगे।

विभाग के अनुसार, पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद, वाहन मालिक पोर्टल पर अपने चालान की स्थिति देख सकेंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल एक बंदी है, और इसके लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा । पुराने चालान दोबारा नहीं खोले जाएँगे।

नई पहल के तहत, इन लंबित चालानों का निपटारा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटल रूप से किया जाएगा। आकाशवाणी लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।

****

मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में उन्नीस सितम्बर तक कहीं–कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच, प्रदेश के कई जिलों में रुक–रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में कई नदियां उफान पर हैं। गंगा और घाघरा नदी बलिया जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

****

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म 'चलो जीते हैं' आज से दो अक्टूबर तक देशभर में पुनः प्रदर्शित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि यह फिल्म स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों को एक सिनेमाई श्रद्धांजलि है। यह फिल्म देशभर के लगभग पांच सौ सिनेमाघरों और स्कूलों में दिखाई जाएगी।

****